समक्ष: जी. आर. मजीठिया, माननीय न्यायमूर्ति

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़, *अपीलकर्ता।*

बनाम

विजय कुमार और अन्य, उत्तरदाता।

आदेश सं 1984 के संख्या 9 से प्रथम अपील।

31 अगस्त, 1989,

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V*) - O. 6, rl.* 15 - मोटर वाहन अधिनियम*, 1939 - धारा 110-A* - लिखित कथन का सत्यापन - *ज्ञान और विश्वास पर आधारित कौन सा पैरा - लिखित कथन सही ढंग से सत्यापित नहीं है - दावेदार का कथन कि, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है - कोई क्रॉस-एग्जामिनेशन नहीं--- क्लेयनम टीएसएस कथन* सही के रूप में स्वीकार किया *जाता है।*

अभिनिर्णित किया की लिखित बयान की अन्तरवस्तु को सत्यापित करने वाले व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्यापित किया गया था। लिखित बयान से यह समझ में नहीं आता है कि जिस व्यक्ति ने लिखित बयान को सत्यापित किया था, वह ऐसा करने के लिए सक्षम था। लिखित बयान को नागरिक प्रक्रिया संहिता के ओ. 6 आरएल -15 (पंजाब और हरियाणा संशोधन द्वारा संशोधित) के तहत सत्यापित किया जाना है। इसे दलीलों के क्रमांकित पैराग्राफ के संदर्भ में सत्यापित किया जाना है और सत्यापन करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसने अपनी जानकारी से किस हिस्से को सत्यापित किया है और प्राप्त जानकारी पर किस हिस्से को सच माना जाता है। सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सत्यापन से यह पता नहीं चलता है कि सत्यापन करने वाले व्यक्ति ने किस आधार पर लिखित बयान में कहा था। अपीलकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान को सही ढंग से सत्यापित नहीं

माना जाएगा और यह कानून की नजर में कोई लिखित बयान नहीं है।
(पैरा 91)

द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ ***बनाम*** विजय कुमार
और अन्य (जी आर मजीठिया, जे।

अभिनिर्णित किया कि यह साक्ष्य का अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि एक पक्ष को अपने प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी के गवाहों को अपने मामले के बारे में इतना कुछ रखना चाहिए जितना कि उस विशेष गवाह से संबंधित है। यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो न्यायालय यह मान लेते हैं कि गवाह का विवरण स्वीकार कर लिया गया है। यदि यह सुझाव देने का इरादा है कि एक गवाह किसी विशेष बिंदु पर सच नहीं बोल रहा था, तो उसका ध्यान पहले क्रॉस-एग्जामिनेशन द्वारा तथ्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि उसे स्पष्टीकरण देने
का अवसर मिल सके। इसके आलोक में, यह माना जाना चाहिए कि इस गवाह के साक्ष्य के इस हिस्से को कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, को कभी भी क्रॉस-एग्जामिनेशन में चुनौती नहीं दी गई थी और एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गवाह का बयान कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, को सही माना गया था।

श्री बी एस नेहरा, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चंडीगढ़ के न्यायालय के *दिनांक 1* जून, *1983* के आदेश से प्रथम अपील *में इस दावा याचिका को स्वीकार करते हुए यह कहा गया था कि दावेदार प्रतिवादी संख्या 1 ओर 2 से* 16,940 रुपये, *की राशि वसूली का हकदार जो मुआवजे के रूप में संयुक्त रूप से और अलग-अलग इस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे आवेदक की तारीख से इसकी वसूली तक मुआवजे की राशि पर* 10 प्रतिशत *ब्याज का* हकदार होगा, और यदि राशि *का भुगतान 2* महीने के भीतर नहीं किया जाता है और *दावेदार को इस याचिका की लागत के लिए भी पात्र बनाया जाएगा।*

दावा: मोटर वाहन की *धारा 110-ए के तहत मुआवजा प्रदान करने के लिए आवेदन*

अपील में दावा: - निचली अदालत के आदेश को पलटने के लिए।

क्रॉस ऑब्जेक्शन नं. 13 सीआईआई, *1984*

आदेश 41 नियम *22* सी.पी.सी. के तहत क्रॉस आपत्तियां, *प्रार्थना करते हुए कि उपरोक्त परिस्थितियों में और न्याय, समानता और निष्पक्ष खेल के हित में, क्रॉस-आपत्तियों की अनुमति दी जाए और अपील को खारिज कर दिया जाए और ट्रायल कोर्ट के फैसले को लागत के साथ*

रद्द कर दिया जाए।

अपीलकर्ता की ओर *से अधिवक्ता एलएम सूरी।*

आर. के. बट्टस, एडवोकेट अंजलि कपूर, एडवोकेट, प्रतिवादी *नंबर* 1 और 3 के लिए

एस. के. लांबा, वकील, प्रतिवादी *संख्या 2 के लिए*

निर्णय

(1)न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मुआवजा देने के लिए दावा आवेदन की अनुमति देने वाले मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी है। प्रतिवादी संख्या 2 (इसके बाद दावेदार के रूप में संदर्भित) ने निम्नलिखित आधारों पर मुआवजा देने के लिए ट्रिब्यूनल का रुख किया: -

(2) 28 फरवरी, 1980 को दावेदार अपने यात्री का स्कूटर चला रहा था, जिसका पंजीकरण नंबर था। डीएचएच-245 चंडी मंदिर की तरफ से कमांड अस्पताल जा रहे थे। उन्होंने उचित हाथ संकेत देने के बाद एक दाईं ओर मोड़ लिया। ट्रैफिक लाइट ने उसके लिए हरी झंडी दिखाई। जैसे ही वह सेक्टर 28 की ओर मुड़ा, प्रतिवादी नंबर 1 विजय कुमार, जो येज्दी मोटरसाइकिल की सवारी कर रहा था, जिसका पंजीकरण नंबर था। सीएचजी -8078 ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गिरकर घायल हो गया। उन्हें वहां से गुजर रहे सैन्य वाहन से अस्पताल ले जाया गया। उन्हें मेडिकल मॉललस के फ्रैक्चर और 5 वें मेटा-कार्पल बाएं हाथ के फ्रैक्चर का सामना करना पड़ा। वह 28 फरवरी, 1980 से 14 मार्च, 1980 तक अस्पताल में रहे। उनकी पत्नी को मामूली चोटें आई हैं।

(3)दावा याचिका को अपीलकर्ता और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा चुनौती दी गई थी। उन्होंने अलग-अलग लिखित बयान दायर किए हैं, लेकिन दलीलें लगभग समान हैं। प्रतिवादी नंबर 1 ने दलील दी कि वह ट्रिब्यून की तरफ से टिम्बरमार्केट की ओर सड़क पर आगे बढ़ रहा था। वह सड़क के बाईं ओर था। जब वह पेट्रोल पंप के क्रॉसिंग पर पहुंचे तो उन्होंने हरी बत्ती देखी और सीधे आगे बढ़ गए। क्रॉसिंग के 3/4 हिस्से को कवर करने के बाद, दावेदार औद्योगिक क्षेत्र से आया और अचानक एक मोड़ लिया

जब प्रकाश का सिग्नल लाल था और उसकी मोटर साइकिल से टकरा गया। यह दुर्घटना दावेदार की लापरवाही के परिणामस्वरूप हुई जब उसने सिग्नल लाल होने पर मुख्य सड़क पर क्रॉसिंग में प्रवेश किया और यह पता लगाने की परवाह नहीं की कि मुख्य सड़क पर यातायात है या नहीं। प्रतिवादियों ने इस बात पर विवाद नहीं किया कि दुर्घटना में शामिल मोटर साइकिल का अपीलकर्ता के साथ बीमा किया गया था।

(4) पक्षकारों की दलील के आधार पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे

(1) क्या दुर्घटना मोटर साइकिल संख्या 12 के तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी? सीएचजी 8078 प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा संचालित है जिसके परिणामस्वरूप दावेदार को चोटें आई हैं? ओ.पी.पी.

(2) दावेदार कितने मुआवजे का हकदार है और प्रतिवादियों में से किससे? ओ.पी.पी.

(3) राहत।

(5) सबूतों की सराहना करने पर ट्रिब्यूनल ने एक ठोस निष्कर्ष दिया कि दुर्घटना प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा मोटर साइकिल के तेज और नीरस ड्राइविंग के परिणामस्वरूप हुई थी। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने माना कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास दुर्घटना की तारीख पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। मुद्दा संख्या 2 के तहत, ट्रिब्यूनल ने कहा कि दावेदार मुआवजे के रूप में 16,940 रुपये की वसूली का हकदार है।

(6) अपील में, अपीलकर्ता के विद्वत वकील ने दुर्घटना या जिस तरीके से यह हुआ था, उस पर विवाद नहीं किया। उन्होंने दावेदार को दिए गए मुआवजे की मात्रा पर भी विवाद नहीं किया। उन्होंने केवल यह सवाल किया कि एश्योरेंस कंपनी के खिलाफ इस कारण से फैसला पारित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना की तारीख पर विजय-कुमार निराश नंबर 1 के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था।

(7) रिकॉर्ड पर पेश किए गए सबूतों की जांच करने पर, मुझे विद्वत वकील की प्रस्तुतियों में कोई आधार नहीं मिला।

(8) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से लिखित बयान उसी वकील के माध्यम से दायर किए गए थे। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने लिखित बयान में यह दलील नहीं दी कि दुर्घटना की तारीख पर उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हालांकि, लिखित बयान के पैरा 25 में प्रतिवादी नंबर 2 ने इस प्रकार अनुरोध किया: -

> "जवाब देने वाला प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है क्योंकि प्रतिवादी नंबर 1 के पास कोई लाइसेंस नहीं था और यदि बीमित व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया गया है और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 96 के तहत उसकी अनुपस्थिति में, कंपनी का कोई दायित्व नहीं है।

(9) लिखित बयान के दावे को सत्यापित किया गया था - सत्यापित करने वाले व्यक्ति के ज्ञान और विश्वास के अनुसार, यह लिखित बयान से समझ में नहीं आता है कि लिखित बयान को सत्यापित करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए सक्षम था। लिखित बयान को नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 15 (पंजाब और हरियाणा संशोधन द्वारा संशोधित) के तहत सत्यापित किया जाना है। इसे दलीलों के क्रमांकित पैराग्राफ के संदर्भ में सत्यापित किया जाना है और सत्यापन करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह अपने ज्ञान से किस हिस्से की पुष्टि करता है और गठन में किस हिस्से को प्राप्त किया गया और उसे सच माना गया। सत्यापन बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सत्यापन से यह पता नहीं चलता है कि सत्यापन करने वाले व्यक्ति ने किस आधार पर लिखित बयान में कहा था। अपीलकर्ता द्वारा दायर लिखित बयान को सही ढंग से सत्यापित नहीं माना जाएगा और यह कानून की नजर में कोई लिखित बयान नहीं है। जैसा कि यह हो सकता है, फाइल का अनुकूलन-मामलों की भयानक स्थिति को प्रकट करता है। प्रतिवादी नंबर 1 अपने गवाह के रूप में मुकदमे में पेश हुआ और एग्जामिनेशन-इन-

चीफ में, उसने कहा कि दुर्घटना के समय उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, "एश्योरेंस कंपनी ने इस बिंदु पर उससे जिरह नहीं की। उनसे केवल एक ही सवाल पूछा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस कहां है और गवाह ने कहा कि यह पुलिस के पास है। उनके वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बयान को जिरह में कभी चुनौती नहीं दी गई। उन्हें कभी कोई सुझाव नहीं दिया गया कि उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। यह सबूत ोंं का एक स्थापित नियम है कि एक पक्ष को अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रत्येक गवाह के सामने अपने मामले के बारे में इतना कुछ रखना चाहिए जितना कि उस विशेष गवाह से संबंधित है। यदि ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, तो न्यायालय यह मान लेते हैं कि गवाह का विवरण स्वीकार कर लिया गया है। यदि यह सुझाव देने का इरादा है कि एक गवाह किसी विशेष बिंदु पर सच नहीं बोल रहा था, तो उसका ध्यान पहले क्रॉस-एग्जामिनेशन द्वारा तथ्य की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए ताकि उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके। इसके आलोक में यह माना जाना चाहिए कि इस गवाह के साक्ष्य के इस हिस्से कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, को जिरह में कभी चुनौती नहीं दी गई और एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गवाह का यह बयान कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था, को सही माना गया था।

(10)यह साबित करने के लिए कि प्रतिवादी एन के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, थेडापलेंटेलेड साक्ष्यकर्ता। प्रतिवादियों ने अपने वकील के माध्यम से मुकदमे में निम्नलिखित गवाहों को तलब किया

(1) लाइसेंसिंग प्राधिकरण के कार्यालय यूटी चंडीगढ़ के कार्यालय ने उपायुक्त चंडीगढ़ के माध्यम से विजय कुमार पुत्र कुलवंत राय, एच. नंबर 2177/37, चंडीगढ़ के लिए आवेदन के साथ उनके पक्ष में ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 102 और 12 अप्रैल, 1980 तक वैध जारी किया था। वह उक्त लाइसेंस जारी करने की प्रविष्टि दर्शाने वाला संबंधित रजिस्टर भी लाएं।

(2) श्री विजय कुमार पुत्र श्री कुलवंत राय पुत्र वेफे के इलेक्ट्रिकल्स, एससीओ 30/23-सी, चंडीगढ़ अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाने के लिए ।

(3) श्री टी.सी.गुप्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सह-पंजीकरण प्राधिकरण, चंडीगढ़ ने ड्राइविंग लाइसेंस सं 2008-09 से संबंधित फाइल के साथ। सीएच-102 12 अप्रैल, 1980 तक विजय कुमार पुत्र कुलवंत राय हाउस नंबर 2177/34-सी, चंडीगढ़ के नाम पर वैध है, जिसमें कार्यालय में संबंधित रजिस्टर में इसके संबंध में प्रविष्टि भी शामिल है।

श्री **टी.सी.** गुप्ता, कार्यकारी मजिस्ट्रेट-सह-रेफिंग प्राधिकरण, चंडीगढ़ अदालत में पेश हुए, लेकिन उनसे पूछताछ नहीं की गई। वही चडीगढ़ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मो. अकरम की जांच RVV.4 के रूप में की गई थी। उन्होंने कहा कि रजिस्टर के सीनियर नंबर 102 पर तलब रजिस्टर में एक प्रविष्टि मौजूद थी, जिसके अनुसार स्कूटर के लिए लाइसेंस विजय कुमार पुत्र कुलवंत राय के पक्ष में जारी किया गया था, लाइसेंस की वैधता 13 अप्रैल, 1977 से 12 अप्रैल, 1980 तक थी। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जांच किए गए इस गवाह से एश्योरेंस कंपनी के वकील द्वारा जिरह की गई थी, लेकिन इस गवाह की गवाही को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं निकाला गया था। इस गवाह के साक्ष्य से स्पष्ट है कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास 13 अप्रैल, 1977 से 12 अप्रैल, 1980 की अवधि के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। यह दुर्घटना 28 फरवरी, 1980 को हुई थी। मैं यह उल्लेख करने से खुद को रोक नहीं सकता कि प्रतिवादियों ने सबूतों को तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की लेकिन वे अपने प्रयास में विफल रहे। प्रतिवादी नंबर 1 ने अपने वकील के माध्यम से श्री टी. सी. गुप्ता को विजय कुमार पुत्र कुलवंत राय निवासी मकान नंबर 2177/34-सी, चंडीगढ़ के नाम पर ड्राइविंग लाइसेंस देने से संबंधित रिकॉर्ड के साथ तलब किया। प्रतिवादी नंबर 1 पते पर नहीं रहता था। दावा आवेदन में यह दिखाया गया था कि वह चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में रहता है और यह कभी विवादित नहीं था कि उसका पता

सही तरीके से उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन गवाह को तलब करने के आवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि विजय कुमार पुत्र कुलवंत राय चंडीगढ़ के मकान नंबर 2177 सेक्टर 34 का निवासी था। साक्ष्य के स्तर पर, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं ने एक-दूसरे के साथ मिलकर यह साबित करने का प्रयास किया कि प्रतिवादी नंबर 1 के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, जिसे वे बुरी तरह से विफल कर दिया। उनका आचरण अपमानजनक होने के योग्य था। अपीलकर्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी ऐसी चीज से संपर्क करे जो अस्तित्व में नहीं है। अनाड़ी प्रयास आवेदक के दावे को पराजित करने के लिए था। यदि प्रतिवादी नंबर 1 के पास दुर्घटना की तारीख पर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, तो आश्वासन कंपनी मुआवजे के लिए उत्तरदायी नहीं है। शीर्ष अदालत द्वारा कानून को अच्छी तरह से तय किया गया था और एश्योरेंस कंपनी के मामले को सर्वोच्च न्यायालय के *कामत और एक अन्य* बनाम *अल्फ्रेडो एंटोनियो डो मार्टिंस और अन्य*[1] के फैसले के दायरे में लाने के लिए सबूतों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा था।. मुझे आशा है कि एश्योरेंस कंपनी निष्पक्ष रूप से कार्य करेगी, न कि उस तरीके से जैसा कि उसने इस मामले में किया है।

(11)पूर्वगामी कारणों से, इस अपील को लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। वकील शुल्क 1000 रुपये आंका गया है जो केवल दावेदार को देय होगा। क्रॉस-आपत्तियों को दबाया नहीं गया और तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

पी.सी.जी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक

[1] 1985 A.C.J. 397

होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा